



CELEBRATION - GAIL

Inspired by Hon'ble Prime Minister's vision of promoting #NariShakti and as a tribute to its women employees of the organization, GAIL recently celebrated International Women's Day at its corporate office, Delhi.

Govt gets ₹747 cr from GAIL share buy back



NEW DELHI: The government has received Rs 747 crore from share buy back by state owned GAIL, DIPAM Secretary Tuhin Kanta Pandey said on Friday.

“GAIL Buyback of shares fully subscribed. Government received Rs 747 cr out of total buyback size of Rs 1046 cr,” Pandey tweeted.

Government holding in the company stands at 51.45 per cent.

Under, a company buys its own outstanding shares to reduce the number of shares available in the open market.

Companies buy back shares for a number of reasons such as to increase the value of remaining shares available by reducing the supply or to return surplus cash to shareholders.

The government wants public sector undertakings to either meet their targets for capital expenditure or “reward the shareholder in the form of a dividend” or share buyback.

PTI

आई.एस.पी. लाइसेंस की शर्तों में बदलाव, टैलीकॉम के बाद अब इंटरनेट इक्विपमेंट में भी नो चाइनीज

नई दिल्ली, 19 मार्च (एजेंसी): चाइनीज कम्पनियों को टैलीकॉम नैटवर्क से बाहर रखने के लिए दूरसंचार विभाग ने अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आई.एस.पी.) कम्पनियों के लाइसेंस की शर्तों में बदलाव किया है। 15 जून के बाद कम्पनियां सिर्फ सरकार से मंजूर उपकरण लगा सकेंगी।

अब इंटरनेट नैटवर्क में चाइनीज इक्विपमेंट की नो एंट्री है। आई.एस.पी. कम्पनियां सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस से ही उपकरण लगा सकेंगी। इक्विपमेंट बनाने वाली सभी कम्पनियों को सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।

नैटवर्क अपग्रेड करने के लिए सरकारी अनुमति जरूरी होगी। अभी बहुत सारी छोटी कम्पनियां उपकरणों के लिए चीन की कम्पनियों पर निर्भर



थी, इससे कम्पनियों की लागत थोड़ी बढ़ सकती है लेकिन जानकार मानते हैं कि सुरक्षा कारणों के चलते सरकार ने सही कदम उठाया है।

अभी रेलटेल, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया और गैल सरकारी कम्पनियों के अलावा 700 से ज्यादा छोटी कम्पनियां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम करती हैं।

नई शर्तों से लागत तो बढ़ेगी लेकिन घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आई है।